अमेरिका-चीन ट्रेड वार का क्या होगा भारत समेत दुनिया पर प्रभाव, जानें किसे होगा घाटा-किसे लाभ

दुनिया. एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

विश्व की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों अमेरिका और के बीच व्यापार को लेकर विवाद बढ़ गया। आइये जानते हैं कि अगर उनका गतिरोध व्यापक आर्थिक संघर्ष में बढ़ जाता है तो क्या होगा। इसका असर भारत और शेष विश्व पर क्या होगा कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चीन को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की खपत भी प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैक्स बढ़ाया शुक्रवार को अमेरिका ने 200 बिलियन डॉलर मूल्य के चीनी सामानों पर 25त्न तक टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। यह एक ऐसा कदम जिसने 5,700 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के संभावित रूप से सामानों के व्यापार को प्रभावित किया। इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैक्स (टैरिफ) को लेकर युद्धों का एक और दौर छिड़ गया है। शनिवार को वाशिंगटन ने चीन के शेष सभी आयातों पर टैक्स लगाकर नए दौर का थप्पड़ जड़ दिया है। ये टैक्स लगभग 300 बिलियन डॉलर के व्यापार के सामानों की व्यापक रेंज पर लागू होते हैं।अमेरिका ने तोड़ी वार्ता, चीन को आस अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने हमें चीन से शेष सभी आयातों पर शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि दोनों पक्ष एक समझौते के पास पहुंचने के करीब थे, लेकिन चीन ने फिर से बातचीत करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर चीनी पक्ष लगातार उम्मीद के मुताबिक आवाज उठाता रहा।शनिवार को वार्ता में चीन के मुख्य वार्ताकार वाइस प्रीमियर लियू हे ने कहा कि बातचीत नहीं टूटी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों की बातचीत के दौरान छोटे झटके सामान्य और अपरिहार्य हैं। आगे देखते हुए हम अभी भी आशावादी हैं।इसके विपरीत अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टीव मनुचिन ने कहा कि वर्तमान में बीजिंग के साथ कोई व्यापार वार्ता निर्धारित नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि जून के महीने में जापान में जी-20 आर्थिक समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है।अमेरिका-चीन विवाद की शुरुआत पिछले साल मार्च के महीने में चीन से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने के बाद अमेरिका और चीन ट्रेड वार बढ़ गया। इसके प्रत्युत्तर में चीन ने अरबों डॉलर के अमेरिकी आयात पर टैक्स लगाकर उसका जवाब दिया।वाशिंगटन की मांग के बाद विवाद और बढ़ गया जब चीन ने अमेरिका के साथ 375 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को कम कर दिया। इसके साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, तकनीकी हस्तांतरण और चीनी बाजारों में अमेरिकी वस्तुओं की अधिक पहुंच के लिए सत्यापन योग्य उपाय शुरू किए। इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव एक कारक था जिसने पिछले साल के आखिर में वैश्विक रूप से कमजोर वैश्विक विस्तार में योगदान दिया क्योंकि इस कारण 2019 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान में कटौती की गई।तात्कालिक कदम का प्रभाव टैक्स बढ़ोतरी के ताजा दौर से सबसे ज्यादा प्रभावित चीनी आयात क्षेत्र में बीस बिलियन डॉलर से अधिक श्रेणी के इंटरनेट मॉडेम, राउटर और अन्य डॉटा ट्रांसमिशन डिवाइस सेगमेंट हुए हैं, जो अमेरिका में निर्मित उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले मुद्रित सर्किट बोर्डों के साथ प्रयोग किए जाते हैं।

नाइजर के टैंकर विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हुई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नियामे: नाइजर की राजधानी नियामे में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास छह मई को एक टैंकर ट्रक में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है. एक सरकारी टीवी चैनल ने रविवार देर शाम यह जानकारी दी.

इससे पहले गत मंगलवार को एक सरकारी रिपोर्ट में 60 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी जिसमें 55 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी. यह विस्फोट नियामे हवाई अड्डे से कुछ मीटर दूर हुआ था.

अधिकतर पीड़ित ऐसे थे जो टैंकर के पलट जाने की वजह से उसमें से निकल रहे तेल को इकट्ठा कर रहे थे, तभी टैंकर में विस्फोट हो गया था. नाइजर ने बुधवार से शुक्रवार तक तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था.

स्वीडन में दोबारा खुल सकता है Julian Assange के खिलाफ लगा यौन उत्पीड़न मामला

स्टॉकहोम, एपी। **एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)**

विकीलीक्स संस्थापक जुलियन असांजे को लंदन में इक्वाडोर एंबैसी से हटाए जाने के एक माह बाद स्वीडन इस बात का फैसला लेगा कि असांजे के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला दोबारा खोला जाए या नहीं। हालांकि यह मामला खत्म हो चुका है लेकिन पीड़ित के वकील ने दोबारा जांच शुरू करने का आग्रह किया है।

इसपर स्वीडन के प्रॉसीक्यूटर फैसला लेंगे कि इस मामले में दोबारा जांच शुरू हो या नहीं। पीड़िता के वकील के आग्रह पर इस मामले को दोबारा शुरू किया जा सकता है। हालांकि असांजे ने स्वीडन में किसी यौन उत्पीड़न के अपराध से इंकार किया है। लेकिन अमेरिका में गोपनीय दस्तावेजों को हथिया कर उन्हें सार्वजनिक करने का गंभीर आरोप है। अमेरिका ने इसी मामले में दर्ज मुकदमों को लेकर असांजे के प्रत्यर्पण की मांग की है।

ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट, नवगठित ब्रेक्जिट पार्टी को बढ़त

लंदन, रायटर। एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को 23 मई को होने वाले यूरोपीय यूनियन (ईयू) के संसदीय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। ओपीनियन पोल में उनकी कंजरवेटिव पार्टी महज दस फीसद वोट के साथ पांचवें पायदान पर खिसक गई है। माना जा रहा है कि इससे टेरीजा पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। कंजरवेटिव पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा भी है कि टेरीजा मे अगले हफ्ते पद छोड़ने की अपनी योजना का एलान कर सकती हैं।

टाइम्स अखबार की ओर से कराए गए इस ओपीनियन पोल में निगेल फेराज के नेतृत्व वाली ब्रेक्जिट पार्टी सबसे पंसदीदा दल के तौर पर उभरी है। उसे 34 फीसद लोगों ने पसंद किया है। विपक्षी लेबर पार्टी 16

फीसद वोट के साथ दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन के ईयू के साथ रहने का समर्थन करने वाली लिबरल डेमोक्रेट्स को 15 और ग्रींस को 11 फीसद लोगों ने पसंद किया है। फेराज ने कहा, %ब्रेक्जिट पार्टी के प्रति लोगों में भारी रुचि बढ़ी है क्योंकि लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहना चाहते हैं।% फेराज की पार्टी का गठन इसी साल जनवरी में हुआ था।

ईयू से अलग होने पर असमंजस

ईयू से अलग होने के लिए ब्रिटेन में करीब तीन साल पहले जनमत संग्रह कराया गया था। लेकिन ब्रिटिश नेताओं में इस बात को लेकर अब भी कोई सहमति नहीं बन पाई है कि ब्रिटेन कब और कैसे ईयू से बाहर होगा ? इस बात पर भी असमंजस है कि ब्रिटेन ईयू से बाहर हो या नहीं ? ब्रिटेन को ईयू से गत 29 मार्च को बाहर होने था, लेकिन समझौते को ब्रिटिश संसद से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसे अक्टूबर तक की मोहलत मिली है।

ईयू से हटने के समर्थकों में गिरावट

तीन साल पहले ईयू से ब्रिटेन के अलग होने का समर्थन करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। उस समय जनमत संग्रह में 52 फीसद लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन ताजा सर्वे में यह गिरकर 48 फीसद पर आ गया है।

751 सदस्यीय है यूरोपीय संसद

यूरोपीय संसद 751 सदस्यीय है। इसके सदस्य सीधे चुन कर आते हैं। ये चुनाव 1979 से हर पांच साल पर कराए जा रहे हैं और इसमें यूरोपीय देशों की सियासी पार्टियां हिस्सा लेती हैं। यूरोपीय संसद में ईयू के सभी देशों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला है।